इकनॉमिक टाइम्स

FDI और JV के लिए टेक्सटाइल उद्योग चला यूरोप
06.10.2009
अविनाश नायर, भार्गव त्रिवेदी

अहमदाबाद: भारतीय टेक्सटाइल उद्योग अब कारोबार के लिए नए इलाकों की खोज कर रहा है।
इसकी रणनीति को देखते हुए लगता है कि यूरोप का फैशन सर्किट और तकनीकी रूप से समृद्ध जापान इसके पहले पड़ाव होंगे।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के जरिए रकम जुटाने और संयुक्त उपक्रम के लिए सहयोगी की तलाश करने के प्रयासों के तहत इस महीने के अंत तक टेक्सटाइल उद्योग का एक प्रतिनिधिमंडल पहली बार यूरोप के दौरे पर जा रहा है।

दिलचस्प तथ्य यह है कि यूरोपीय संघ के साथ सरकार भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंजाम देने के प्रयास करने में जुटी है।

कपड़ा मंत्रालय में संयुक्त सचिव जे एन सिंह ने ईटी को बताया, 'इस क्षेत्र में एफडीआई को आकर्षित करने और यूरोपीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के प्रयासों के तहत कपड़ा मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर में इटली, स्विट्जरलैंड और तुर्की की यात्रा पर जा रहा है।' टेक्सटाइल से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस के लिए सिंह अहमदाबाद में मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में कपड़ा जगत की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। ये प्रतिनिधि गारमेंटिंग, प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल मशीनरी प्रोडक्शन में समझौते के प्रयास करेंगे।
यह प्रतिनिधिमंडल कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन की अध्यक्षता में विदेश यात्रा पर जाएगा।

सिंह ने बताया, 'टेक्सटाइल मशीनरी के मामले में स्विट्ज़रलैंड का मजबूत आधार है।

इटली अपने फैशन के लिए मशहूर है जबकि तुर्की प्रोसेसिंग और गारमेंट के मामले में काफी समृद्ध है।'

सिंह फाइबर2फैशन द्वारा आयोजित एक इंटरनेशल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए अहमदाबाद आए थे।

सरकार को उम्मीद है कि अगले तीन सालों में घरेलू टेक्सटाइल उद्योग में कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है।

सिंह ने बताया, 'भारत और यूरोप के बीच मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित बातचीत अहम दौर में पहुंच गई है।'

सिंह ने कहा, 'सरकार जापानी और लातिन अमेरिकी बाजारों में भी पहुंच बनाने की योजना बना रही है।'
इससे पहले कॉन्फ्रेंस में अरविंद लिमिटेड के एमडी संजय लालभाई ने बताया कि यूरोप के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ठोस प्रयास करने चाहिए।

लालभाई ने कहा, 'हमें यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाने की जरूरत है।
भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और द्विपक्षीय प्लेटफॉर्म पर हमारे पास ऑफर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं।

हम उन देशों को दरअसल एक अरब डॉलर का मजबूत बाजार ऑफर कर सकते हैं और इसके बदले उनके बाजार में पहुंच बना सकते हैं।'उन्होंने कहा कि चीन के बाद यूरोपीय बाजार दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।

उन्होंने कहा, 'हम जापान की तरफ भी आशाभरी निगाहों से देख सकते हैं।

चीन धीरे-धीरे महंगा बाजार बनता जा रहा है और जापानी नए बाजारों की तरफ देख रहे हैं।'
घरेलू कपड़ा उद्योग की कमियों की तरफ भी लालभाई ने इशारा किया।

उन्होंने कहा, 'अगर समग्र रूप में देखा जाए तो हमारा कपड़ा उद्योग करीब 40 अरब डॉलर का है, लेकिन इस उद्योग में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका कारोबार एक अरब डॉलर का हो।

इसका मतलब यह है कि यहां सरकार और उद्योग जगत के बीच नेतृत्व एवं साझेदारी के मोर्चे पर कुछ न कुछ कमी है।'

उन्होंने कहा, '2000-2007 में चीन का कपड़ा निर्यात 100 अरब डॉलर से बढ़कर 200 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

इसके साथ ही निर्यात में उसका हिस्सा भी 18 फीसदी से दोगुना होकर 36 फीसदी पर पहुंच गया, जबकि भारतीय उद्योग का निर्यात में हिस्सा तीन फीसदी पर स्थिर है।

इसके पीछे की वजहों को ढूंढकर उनका निदान किए जाने की जरूरत है।'

उन्होंने कहा, 'हमें लागत के मोर्चे पर बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से होड़ करने की जरूरत नहीं है।

हमें तो यूरोप के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी चाहिए जिसके पास दुनिया के कुल बाजार का 29 फीसदी हिस्सा है और जो चीन से थोड़ा ही पीछे है।

यूरोप का बाजार फैशन केन्द्रित है। हमें पूर्वी यूरोप और तुर्की में इस बाजार का हिस्सा हासिल करने की रणनीति तैयार करनी चाहिए।'

http://hindi.economictimes.indiatimes.com/rssarticleshow/msid-5094841,prtpage-1.cms से; यह पेज अब उपलब्ध नहीं होता है।